

मणपुर में आपातकालीन उपबंधों का प्रयोग और भारत की संघीय संरचना

प्रलिस के लयः

आपातकालीन उपबंध, [अनुच्छेद 355](#), [अनुच्छेद 356](#), [राषट्रपतशिसन](#), [भारत के संवधिन की सातवीं अनुसूची](#), [भारत का सर्वोच्च नयायालय](#), [राषट्रीय आपातकाल](#)

मेन्स के लयः

मणपुर आंतरक संकट, भारत की संघीय संरचना और आपातकालीन उपबंध, भारतीय संवधिन

[स्रोत: TH](#)

चर्चा में क्यों?

मणपुर में हाल ही में हुई हसिा ने [केंद्र-राज्य संबंधों](#) और [मणपुर के आंतरक संकटों](#) से नपिटने में केंद्र की भूमकिया पर बहस को फरि से छेड़ दया है तथा ऐसी स्थतरियों में [आपातकालीन उपबंधों](#) के प्रयोग पर प्रकाश डाला है ।

राज्य की सुरक्षा के लयि केंद्र द्वारा आपातकालीन उपबंध क्या हैं?

- **संवधानक आधार:** भारतीय संवधिन के भाग XVIII में स्थतरि [अनुच्छेद 355](#) और [356](#) (अनुच्छेद 352 से 360 तक) आपातकाल के दौरान केंद्र तथा राज्य सरकारों की भूमकियों को परभाषतरि करते हैं ।
 - **अनुच्छेद 355:** यह अधदश जारी करता है ककेंद्र राज्यों को बाह्य और आंतरक अशांतरि (आंतरक संकट) से बचाव करते हुए यह सुनशचतरि करना होगा ककराज्य सरकारें संवधानक रूप से कार्य करें ।
 - **अनुच्छेद 356:** कसीं राज्य में [राषट्रपतशिसन](#) लागू करने की अनुमतरि देतरा है जब उसकी सरकार संवधिन के अनुसार कार्य करने में असमर्थ हो, जससे केंद्र को सीधे नयंत्रण संभालने में सक्षम बनाया जा सके ।

//

आपात उपबंध (Emergency Provisions)

- अनु. 352- आपात की उद्घोषणा
- अनु. 353- आपात की उद्घोषणा का प्रभाव
- अनु. 354- जब आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में है तब राजस्वों के वितरण संबंधी उपबंधों का लागू होना
- अनु. 355- बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्य की सुरक्षा करने का संघ का कर्तव्य
- अनु. 356- राज्यों में सांविधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध
- अनु. 357- अनुच्छेद 356 के अधीन की गई उद्घोषणा के अधीन विधायी शक्तियों का प्रयोग
- अनु. 358- आपात के दौरान अनुच्छेद 19 के उपबंधों के निलंबन
- अनु. 359- आपात के दौरान भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन का निलंबन
- अनु. 359क : (निरसित)
- अनु. 360- वित्तीय आपात के बारे में उपबंध

आपात उपबंध

भारतीय संविधान में तीन प्रकार के आपातकाल का उपबंध हैं-

- (1) राष्ट्रीय आपात (अनुच्छेद 352),
- (2) राष्ट्रपति शासन (अनुच्छेद 356) और
- (3) वित्तीय आपात (अनुच्छेद 360) ।

नोट: भारत एक **संघ** है जिसमें **केंद्र और राज्य सरकारें** शामिल हैं। भारतीय संविधान की **सातवीं अनुसूची** संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण करती है।

- **भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची** के अंतर्गत 'पुलिस' व 'लोक व्यवस्था' राज्य के विषय हैं और इसलिये अपराध को रोकना, उसका पता लगाना, अपराध को रजिस्टर करना, जाँच करना तथा अपराधियों पर मुकदमा चलाना राज्य सरकारों का प्राथमिक कर्तव्य है।

मण्डल की स्थिति पर आपातकालीन उपबंध किस प्रकार लागू होता है?

- **संकट की गंभीरता:** मण्डल में व्यापक हिसा (जिसमें नागरिकों पर हमले और पुलिस शस्त्रागारों की लूट शामिल है) बताती है कि वहाँ स्थिति **वधि-व्यवस्था की सामान्य स्थिति से भी अधिक गंभीर** हो गई है।
 - यह गंभीरता दर्शाती है कि इन परिस्थितियों में आपातकालीन उपबंधों को लागू करना उचित नरिणय हो सकता है।
- **राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया जाना:** हिसा की गंभीर प्रकृति के बावजूद, अनुच्छेद 356 के तहत **राष्ट्रपति शासन लागू नहीं** किया गया है।
 - अनुच्छेद 356 का प्रयोग न किये जाने से यह चिंता उत्पन्न होती है कि क्या राजनीतिक कारक संकट से नपिटने की प्रतिक्रिया को प्रभावित कर रहे हैं।
- **अनुच्छेद 355 का अनुप्रयोग:** केंद्र द्वारा **अनुच्छेद 355** के तहत कदम उठाया रहा है, जिसमें यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि राज्यों को संवैधानिक रूप से संरक्षण और शासति किये जाए।
 - हालाँकि आलोचकों का तर्क है कि अब तक की कार्रवाई **संकट के पैमाने को प्रभावी ढंग से नपिटने के लिये पर्याप्त नहीं** हो सकती है।
 - इस मामले में अनुच्छेद 355 का प्रयोग वधि-व्यवस्था पुनरस्थापति करने तथा चल रही हिसा से नपिटने के लिये अधिक नरिणायक उपायों की आवश्यकता को रेखांकित करता है।

अनुच्छेद 355 और 356 के संबंध में क्या नरिणय हैं?

- **ऐतहासिक दुरुपयोग:** भारतीय संविधान के प्रमुख नरिमाता **डॉ. बी.आर. अंबेडकर** को उम्मीद थी कि **अनुच्छेद 355 और 356** अपरयुक्त रहेंगे तथा 'नरिसति उपबंध' बन जाएंगे।
 - इस लक्ष्य के बावजूद, **अनुच्छेद 356 का कई बार दुरुपयोग** हुआ है, जिसके परिणामस्वरूप राजनीतिक एजेंडा और वधि-व्यवस्था बनाए रखने की चिंताओं जैसे विभिन्न कारणों से **नरिवाचति राज्य सरकारों को बरखास्त कर दिया** गया है।
- **एस.आर. बोमई मामला, 1994:** **भारत के सर्वोच्च न्यायालय** के इस ऐतहासिक नरिणय ने **अनुच्छेद 356** के दुरुपयोग को बहुत हद तक प्रतबंधित कर दिया। न्यायालय ने नरिणय सुनाया कि **राष्ट्रपति शासन केवल संवैधानिक तंत्र के वधितन की स्थिति में ही लागू किया जाना चाहिये**, न कि केवल कानून और व्यवस्था के मुद्दों के लिये।
 - इसने यह भी अभनरिधारति किये कि इस प्रकार के अध्यापण न्यायिक समीक्षा के अधीन हैं, तथा यह सुनिश्चित किये गया कि **अनुच्छेद 356 का प्रयोग राजनीतिक उद्देश्यों के लिये नहीं किया जाएगा**।
 - सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संवैधानिक तंत्र के असफल हो जाने का अर्थ है कि राज्य में प्रशासन का संचालन वास्तव में असंभव है, न कि कोई साधारण समस्या।

- **अनुच्छेद 355 का वसितार:** अनुच्छेद 356 पर न्यायिक परतर्बिंध थे, जबकि अनुच्छेद 355 का दायरा बढ़ाया गया है। शुरु में सर्वोच्च न्यायालय की अनुच्छेद 355 की व्याख्या सीमिति थी, जो प्रायः इसे अनुच्छेद 356 के प्रयोग से जोड़ती थी।
 - हालाँकि 1998, 1997 जैसे मामलों में न्यायालय ने नरिवचन को व्यापक बनाया।
 - संशोधति दृषटकिण संघ को राज्यों की सुरक्षा के लिये व्यापक कार्रवाई करने तथा यह सुनश्चिति करने की अनुमति देता है कि उनका शासन संवैधानकि सदिधांतों के अनुरूप हो।

अनुच्छेद 355 और अनुच्छेद 356 के संबंध में क्या सफिरशिनैं हैं?

- **सरकारिया आयोग (वर्ष 1987):** न्यायमूरतरणजीत सहि सरकारिया की अधयकषता वाले इस आयोग ने सफिरशि की थी कि अनुच्छेद 356 का प्रयोग बहुत सावधानी से कया जाना चाहयि, केवल अत्यंत दुर्लभ परस्थितियों में तथा कसिी राज्य में संवैधानकि तंत्र के असफल हो जाने की स्थिति को हल करने और टालने के लिये सभी संभावति वकिल्पों को समाप्त करने के बाद अंतमि उपाय के रूप में।
- **संवधान के कार्रकरण की समीक्षा के लिये राष्ट्रिय आयोग (वर्ष 2002) और पुंछी आयोग (वर्ष 2010):** आयोग ने राय दी है कि अनुच्छेद 355 संघ पर एक कर्ततव्य अध्यारोपति करता है और उसे आवश्यक कार्रवाई करने की शक्ति प्रदान करता है तथा अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन अंतमि उपाय के रूप में प्रयोग कया जाना चाहयि।
 - **पुंछी आयोग** ने अनुच्छेद 355 और 356 के अंतरगत 'स्थानीय आपातकालीन उपबंधों' का प्रस्ताव रखा है, जसिके तहत पूरे राज्य के बजाय कसिी ज़िले या उसके कुछ हसिसों जैसे स्थानीय कषेत्रों को राज्यपाल शासन के अधीन रखा जा सकता है। यह स्थानीय आपातकाल तीन महीने से अधिकि नहीं चलना चाहयि।

राष्ट्रपति शासन और राष्ट्रिय आपातकाल में क्या अंतर है?

राष्ट्रपति शासन (अनुच्छेद 356)	राष्ट्रिय आपातकाल (अनुच्छेद 352)
इसकी घोषणा तब की जा सकती है जब कसिी राज्य की सरकार संवधान के प्रावधानों के अनुरूप नहीं चल पाती है। इसका संबंध युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र वदिरोह से नहीं है।	राष्ट्रिय आपातकाल केवल तभी घोषति कया जा सकता है, जब भारत या उसके कसिी भाग की सुरक्षा को युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र वदिरोह से खतरा हो।
इस दौरान, राज्य कार्यपालिका को बरखास्त कर दिया जाता है और राज्य वधिानमंडल को नलिंबति या भंग कर दिया जाता है। <ul style="list-style-type: none"> • राष्ट्रपति राज्यपाल के माध्यम से राज्य का प्रशासन संभालता है तथा संसद राज्य के लिये कानून बनाती है। • संकषेप में राज्य की कार्यकारी और वधायी शक्तियाँ केंद्र सरकार में नहिति होती है। 	इस दौरान, राज्य कार्यपालिका और वधायिका संवधान के प्रावधानों के तहत प्रदान की गई शक्तियों के अनुरूप कार्य करना जारी रखती है। <ul style="list-style-type: none"> • इसके तहत केंद्र को राज्य प्रशासन और कानून बनाने की समवर्ती शक्तियाँ प्राप्त हो जाती हैं।
इसके तहत संसद राज्य के लिये कानून बनाने की शक्ति राष्ट्रपति या कसिी अन्य नरिदषिट प्राधिकारी को सौंप सकती है। <ul style="list-style-type: none"> • आमतौर पर राष्ट्रपति राज्य के लिये सांसदों (MP) के परामर्श से कानून बनाते हैं। इन कानूनों को राष्ट्रपति अधिनियम कहा जाता है। 	संसद राज्य सूत्री के वषियों पर केवल स्वयं ही कानून बना सकती है तथा यह शक्ति कसिी अन्य नकियाय या प्राधिकरण को नहीं सौंप सकती।
राष्ट्रपति शासन के लिये अधिकितम अवधि तीन वर्ष नरिधारति की गई है। <ul style="list-style-type: none"> • इसके बाद, इसे समाप्त कया जाना चाहयि और राज्य में सामान्य संवैधानकि व्यवस्था बहाल की जानी चाहयि। 	राष्ट्रिय आपातकाल के लिये कोई अधिकितम अवधि नरिधारति नहीं है। <ul style="list-style-type: none"> • इसे प्रत्येक छह महीने में संसद की मंजूरी से अनश्चिति काल तक जारी रखा जा सकता है।
इसके तहत केवल आपातकाल के दौरान राज्य का केंद्र के साथ संबंध संशोधति होता है।	इसके तहत केंद्र और सभी राज्यों के बीच संबंधों में बदलाव कया कयि जा सकते हैं।
इसकी घोषणा या इसे जारी रखने का अनुमोदन संसद में केवल साधारण बहुमत से ही पारति कया जा सकता है।	इसकी घोषणा या इसे जारी रखने का अनुमोदन संसद में वशेष बहुमत से ही पारति कया जा सकता है।
इसका नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।	इससे नागरिकों के मौलिक अधिकार प्रभावति होते हैं।
इसे केवल राष्ट्रपति द्वारा ही नरिस्त कया जा सकता है।	लोकसभा इसके नरिसन के लिये प्रस्ताव पारति कर सकती है।

नषिकर्ष

मणपिर में हुई हसिा ने केंद्र-राज्य संबंधों और आपातकालीन प्रावधानों पर वविाद को सुर्खियों में ला दिया है। जबकि अनुच्छेद 355 केंद्र को संकट के समय कार्रवाई करने की अनुमति देता है, अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन का प्रावधान करता है, लेकिन इसका प्रयोग सावधानी से कया जाना चाहयि। मणपिर की स्थिति संवैधानकि दशिा-नरिदेशों का सम्मान करते हुए गंभीर हसिा से नपिटने के लिये नरिणायक कार्रवाई की आवश्यकता को उजागर करती है।

????? ???? ????:

प्रश्न. किसी राज्य की आंतरिक अशांति से निपटने के लिये संवैधानिक उपबंधों का परीक्षण कीजिये। मणपुर में हाल ही में हुई हिसा पर ये प्रावधान किस प्रकार लागू होते हैं?

और पढ़ें: [मणपुर में हिसा](#)

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न (PYQ)

????? ???? ????:

प्रश्न. नमिनलखिति में कौन-सी लोक सभा की अनन्य शक्त(ियाँ) है/हैं? (2022)

1. आपात की उद्घोषणा का अनुसमर्थन करना
2. मंत्रपरिषद के वरिद्ध अवशिवास प्रस्ताव पारित करना
3. भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:

- (a) 1 और 2
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 3
- (d) केवल 3

उत्तर: (b)

प्रश्न. भारत के संवैधानिक संदर्भ में सामान्य वधियों में अंतर्विष्ट प्रतिबंध अथवा निर्बंधन अथवा उपबंध, अनुच्छेद 142 के अधीन सांविधानिक शक्तियों पर प्रतिबंध अथवा निर्बंधन की तरह कार्य नहीं कर सकते। नमिनलखिति में से कौन-सा एक, इसका अर्थ हो सकता है? (2019)

- (a) भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते समय लिये गए निर्णयों को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती।
- (b) भारत का उच्चतम न्यायालय अपनी शक्तियों के प्रयोग में संसद द्वारा निर्मित वधियों से बाध्य नहीं होता।
- (c) देश में गंभीर वित्तीय संकट की स्थिति में भारत का राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के परामर्श के बिना वित्तीय आपात घोषित कर सकता है।
- (d) कुछ मामलों में राज्य वधानमंडल, संघ वधानमंडल की सहमति के बिना, वधि निर्मित नहीं कर सकते।

उत्तर: (b)

प्रश्न. भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में नमिनलखिति कथनों पर विचार कीजिये: (2018)

1. प्रत्येक एम.एल.ए. के वोट का मूल्य अलग-अलग राज्य में अलग-अलग होता है।
2. लोकसभा के सदस्यों के वोट का मूल्य राज्यसभा के सदस्यों के वोट के मूल्य से अधिक होता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1, न ही 2

उत्तर: (b)

????? ????:

प्रश्न. कनि परिस्थितियों में भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा की जा सकती है? ऐसी उद्घोषणा के लागू रहने तक, इसके अनुसरण के क्या-क्या परिणाम होते हैं? (2018)

